



## परसपेक्टवि: भारतीय अंतरिक्ष नीति- 2023

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने [भारतीय अंतरिक्ष नीति- 2023](#) को मंजूरी दी। नीति में कहा गया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में [भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन](#) (ISRO) मुख्य रूप से बाह्य अंतरिक्ष के बारे में और अधिक समझ विकसित करने के लिये नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों के अनुसंधान व विकास के साथ मानव समझ के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- इस नीति को एक भविष्यवादी नीति के रूप में वर्णित किया गया है जो भारत को इस क्षेत्र में स्थापित करेगी और 21 वीं सदी में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को लॉन्च करेगी।

### नीतिकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

यह नीति चार अलग-अलग, लेकिन संबंधित संस्थाओं का निर्माण करती है, जो आमतौर पर इसरो के पारंपरिक डोमेन रही गतिविधियों में नज्दी क्षेत्र की अधिक-से-अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी।

- [InSPACE \(भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र\)](#): यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण, लॉन्च पैड स्थापित करने, उपग्रहों को खरीदने और बेचने, और अन्य चीजों के बीच उच्च-रिज़ोल्यूशन डेटा का प्रसार करने के लिये एकल खड़की मंजूरी और प्राधिकरण एजेंसी होगी।
  - यह NGEs (गैर-सरकारी संस्थाओं और इसमें नज्दी कंपनियों) और सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करेगा।
- [न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड \(NSIL\)](#): यह सार्वजनिक व्यय के माध्यम से बनाई गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों के व्यावसायीकरण के साथ-साथ नज्दी या सार्वजनिक क्षेत्र से अंतरिक्ष घटकों, प्रौद्योगिकियों, प्लेटफार्मों और अन्य संपत्तियों के निर्माण, पट्टे या खरीद के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- [अंतरिक्ष विभाग](#): यह समग्र नीति दिशानिर्देश प्रदान करेगा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिये नोडल विभाग होगा और अन्य बातों के अलावा, विदेश मंत्रालय के परामर्श से वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन और कार्यक्रमों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय का समन्वय करेगा।
  - अंतरिक्ष गतिविधि से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिये यह एक उपयुक्त तंत्र भी बनाएगा।

### नज्दी क्षेत्र की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

- [वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये](#): वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 2% से कम है और अंतरिक्ष नीति भविष्य में इसे 10% तक बढ़ाने में मदद करेगी।
  - यह नीति अंतरिक्ष सुधारों में बहुत आवश्यक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी और देश के लिये अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अवसरों को चलाने के लिये नज्दी उद्योग की भागीदारी को बढ़ाएगी।
- [अंतरिक्ष अन्वेषण](#): नज्दी कंपनियों को अंतरिक्ष मशिन करने की अनुमति देने से नज्दी क्षेत्र के नविश को बढ़ावा देकर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को लाभ हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, स्पेसएक्स का पुनः प्रयोज्य (Re-usable) फाल्कन 9 रॉकेट दुनिया भर के अंतरिक्ष मशिनों के लिये एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है।
- [अंतरराष्ट्रीय प्रतस्पर्द्धात्मकता](#): अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ती वैश्विक रुचि के साथ, नज्दी कंपनियाँ देशों को उद्योग में प्रतस्पर्द्धा बने रहने में मदद कर सकती हैं।
- [लचीलापन](#): सरकारी एजेंसियों की तुलना में नज्दी कंपनियाँ अक्सर अधिक चुस्त और अनुकूलनीय होती हैं, जिससे उन्हें बाज़ार की बदलती मांगों और तकनीकी प्रगति के लिये अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिलती है।

### इस नीतिकी महत्व क्या है?

- [भारत के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के लिये महत्वपूर्ण कदम](#): नीति अंतरिक्ष उद्योग के मानकों को विकसित करेगी, चहिनति अंतरिक्ष

